बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा की हालत खराब

पॉलिसी से चलनेवाला स्टेट नहीं बन पाया झारखंड

हफ्ते की बात

परिमल नथवाणी, राज्यसभा सांसद

झारखंड से 2008 में राज्यसभा सांसद चुने गये परिमल नथवाणी का मानना है कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी को विकास से मतलब नहीं रहा. शासन ने विकास की इच्छाशक्ति नहीं दिखायी. झारखंड की समस्याओं को लगातार संसद में उठानेवाले परिमल नथवाणी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट भी हैं. कहते हैं कि झारखंड पॉलिसी से चलनेवाला राज्य नहीं बन पाया. **प्रभात खबर** के वरीय संवाददाता **आनंद मोहन** ने उनसे राज्य की समस्याओं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका सहित कई मुद्दों पर लंबी बातचीत की. प्रस्तुत हैं इसके प्रमुख अंश.

पिछले तीन-चार वर्षों से झारखंड को देख-समझ रहे हैं. झारखंड आज कहां खड़ा है?

जब मैं सांसद चुना गया था और आज के झारखंड में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता. विकास रुक गया है. राज्य में ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी है. गांवों में जाता हूं, तो लगता है कि हमने कुछ हासिल नहीं किया. लोगों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं. बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत खराब है. शहरों में कुछ नयी इमारतें जरूर बनी हैं, लेकिन वह बिल्डर प्रोफेशन का काम है. लॉ एंड आर्डर में भी सुधार नहीं दिखता है. राज्य जैसे स्थिर है.

आखिर समस्या की जड़ में क्या है?

शासन ने विकास की इच्छाशक्ति नहीं दिखायी. राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास नहीं हो सका. यह राज्य कभी भी टू पार्टी रूलिंग स्टेट नहीं रहा. शासन में अनुशासन की कमी रही. ब्यूरोक्रेसी को विकास से मतलब नहीं रहा. ये लोग रूटीन टाइप काम करते रहे.

शेष पेज 19 पर

PRABHAT KHABAR
Pg. 01 Dt 27/11/2011

पेज एक का शेष

पॉलिसी से ...

गुजरात से आपका संबंध है. झारखंड और गुजरात में क्या फर्क है?

गुजरात पॉलिसी से चलता है. झारखंड पॉलिसी पर चलनेवाला स्टेट ही नहीं बन पाया. हम विकास के लिए नीतियां नहीं बनाये. कोई रोड मैप तैयार नहीं किया: गुजरात में बदलाव सरकार की नीतियों और इच्छाशक्ति से हुआ. निवेशकों का रूझान बढ़ा. वहां सरकार ने उद्योग के लिए माहौल बनाये. जमीन उपलब्ध कराये. गुजरात में जीआइडीसी के माध्यम से जमीन का अधिग्रहण हुआ. नीतियां ऐसी बनी, जिससे लोगों को नुकसान नहीं हुआ. झारखंड में स्थिति दूसरी है. यहां उद्योग लगाने के लिए कंपनियों को खुद जमीन खरीदने को कहा जा रहा है. इससे जमीन देनेवालों को भी नुकसान है. विधि-व्यवस्था और आधारभूत संरचना को अनुकूल बनाने का प्रयास नहीं हुआ.

हालात कैसे बदलेंगे. झारखंड रास्ते पर कैसे आये?

झारखंड समृद्ध राज्य है. हम बिहार के साथ थे, तो लग रहा था कि पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है. स्थानीय लोगों का विकास नहीं हो रहा. जयपाल सिंह मुंडा से लेकर शिबू सोरेन तक ने संघर्ष किया. राज्य मिल गया, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर हम अपने कामकाज से पहचान नहीं बना सके. केवल सरकार चलाने के नाम पर सरकार चलती रही. राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा. विकास के लिए जनता को भी सचेत होना होगा. किसी एक पार्टी को बहुमत देना होगा. जनता को तय करना होगा कि उनके हित में क्या है. विकास का माहौल बनाने के लिए सरकार सभी पार्टियों के साथ बैठक करे. राज्य में जहां जमीन अधिग्रहण की समस्या नहीं है, इंडस्ट्रियल जोन घोषित करे. इंडस्ट्रियल पार्क बना सकते हैं. आधारभूत संरचना मजबूत करनी होगी. उद्योगों को भी अपना माइंड सेट बदलने की जरूरत है. जरूरी नहीं है कि जहां खदान हो, वहीं इंडस्ट्री लगे. जंगलों को खाली कर, आदिवासियों को विस्थापित कर माइंस के इलाके में ही उद्योग लगाने की जरूरत नहीं है. दूसरी जगहों पर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन रोजगार भी सृजित होंगे.

औद्योगिक नीतियां कैसी हो, गांवों तक विकास कैसे पहुंचे?

औद्योगिक नीतियां यहां के सामाजिक-आर्थिक दशा को देखते हुए बने. पार्टी-पॉलिटिक्स से हट कर नीति बनाने की जरूरत है. यहां के संसाधन राज्य की पूंजी है. मिनरल्स को बाहर जाने से रोकना चाहिए. खनिज संपदा बाहर चले जायेंगे, तो हम आनेवाली पीढ़ी को क्या देंगे. राज्य के संसाधन का दोहन नहीं होना चाहिए. यहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले. दूसरी तरफ गांव पर भी ध्यान देने की जरूरत है. गांव जितना मजबूत होगा, झारखंड मजबूत होगा. गांव को आबाद किये बिना, झारखंड खुशहाल नहीं हो सकता है. ग्राम सभा को सरकार मजबूत करे. गांवों में चेक डैम बने, सड़कें हो, बिजली पहुंचे. फिर देखिए पलायन कैसे रुकता है.

बाहर से आये कई लोग झारखंड से राज्यसभा पहुंचते रहे हैं. पर सांसद बनने के बाद राज्य में बहुत रुचि नहीं दिखायी. आप भी गुजरात से आये, राज्य की राजनीति से लेकर दूसरे मुद्दों पर गहरी रुचि दिखा रहे हैं. कोई पॉलिटिकल एजेंडा ?

मैं राज्य की राजनीति में रुचि नहीं दिखा रहा. किसी पॉलिटिकल एजेंडे के साथ नहीं आया. हां यहां के विकास और समस्याओं पर रुचि जरूर दिखा रहा हूं. एक एमपी होने के नाते, मुझसे जितना बन रहा है, मैं कर रहा हूं. मैं यहां से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा. राज्य की जनता का मुझ पर उपकार है. राज्य के एमएलए ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं. इस लिहाज से जनता के प्रति मेरे भी कर्तव्य हुए. इसी को पूरा करना चाहता हूं. मैं कोई काम दिल से करता हूं. दिल्ली में रह कर मैं चाहता, तो यहां एमपी फंड भेज कर काम कराता. समय देने की जरूरत नहीं थी. लेकिन यह जनता और मुझ पर विश्वास जतानेवालों के साथ धोखा होता. मैं यहां के लोगों से मिल कर उनके दु:ख-दर्द को दूर करना चाहता हूं. पूरा समय देना चाहता हूं. प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन संतोष नहीं है. अभी इस राज्य के लिए बहुत कुछ करना है.

राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि पार्टी बनायेंगे या फिर किसी दल में शामिल होंगे?

ऐसा कतई नहीं है. मैं राज्य के लिए हर राजनीतिक दल व नेताओं के साथ हूं. एक सांसद के रूप में मेरी जहां जरूरत है, साथ देने के लिए तैयार हूं. राज्य की छवि सुधारने और विकास के रास्ते ले जाने के लिए सभी इच्छुक राजनेताओं के साथ खड़ा रहूंगा.

झारखंड जैसे छोटे राज्यों की संसद के अंदर बहुत सुनी नहीं जाती. यहां के सांसद बहुत मुखर भी नहीं हैं?

ऐसा नहीं है कि संसद के अंदर सुनी नहीं जाती. हमारे सांसद मामले भी उठाते हैं. बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, इंदर सिंह नामधारी, पीएन सिंह जैसे सक्षम नेता हैं. फिर हमारे यहां से तो केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय हैं. मेरा मानना है कि झारखंड के कोर मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग हट कर इकट्ठा होने की जरूरत है. हम एक साथ मुद्दों को उठायेंगे, तो दिल्ली भी हमारी सुनेगी.

आप लोकपाल मसौदे के लिए बनायी गयी स्टैंडिंग कमेटी में हैं? लोकपाल को लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है?

भ्रष्टाचार देश की जटिल समस्या है. यह एक दिन में खत्म होनेवाली बीमारी नहीं है. इसकी जड़ें गहरी हैं. मेरा मानना है कि देश में सक्षम लोकपाल हो. लोकपाल के आने से भ्रष्टाचार करनेवालों को भय जरूर रहेगा. मेरा यह भी मानना है कि लोकपाल सक्षम हो, लेकिन निरंकुश ना हो. सिस्टम के अंदर काम करे.

लोकपाल बिल वर्तमान सत्र में पारित होने की उम्मीद है?

स्टैंडिंग कमेटी अपने सुझाव भेज देगी. बिल तो सदन को पारित करना है. इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है.

आपने राजधानी में नगर निगम का अस्पताल निजी फंड से बनाया. इसे चलाना भी चाहते थे. मामला कहां फंस गया?

मैं बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल चलाना चाहता था. टोकन मनी पर अस्पताल चलाने की इच्छा थी, जहां गरीबों को एकदम मामूली और सरकार द्वारा तय दर पर इलाज हो सके. मुझे जितनी जगह मिली, उसमें मैंने भवन को निजी फंड से सुंदर बनाने की कोशिश की. मीडिया को याद होगा कि नगर निगम का अस्पताल किस हाल में था. आज वह बन कर तैयार हो गया है. मुझे केवल इस बात का भय है कि उस भवन की हालत पहले जैसी न हो जाये. मैं इसमें चिकित्सा के संसाधन जुटाना चाहता था. इसे राज्य का एक बेहतर अस्पताल बनाने की परिकल्पना थी. इसे कहीं उठा कर ले नहीं जाता. सुना है कि अब विभाग ने टेंडर किया है. मैं व्यवसाय के लिए अस्पताल नहीं चलाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं टेंडर भरूं.

आप देश के एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी से जुड़े हैं. झारखंड में आपकी कंपनी कोई निवेश करने की इच्छा रखती है?

फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है. रिलायंस निवेश करने के लिए आवेदन लेकर दौड़नेवाली कंपनी नहीं है. हमें जिन लोगों ने आदर के साथ और एक पॉलिसी के तहत बुलाया है, गये हैं. झारखंड में मुझे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दिखती है. ऐसे भी कंपनी में बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स हैं. ऐसे फैसले वहीं से होते हैं.

PRABHAT KHABAR
Pg. 19 Dt 27/11/2011